THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

(b) Docs not arise.

(c) The Telecom Advisory Committee (TAC) for Mumbai was reconstituted in December, 1997 shortly after the expiry of its terms on 30.11.1997.

(d) Does not arise.

ओ. एफ. सी. प्रणाली युक्त टेलीफोन एक्सचेंज

2937. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रायगढ़ जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली युक्त टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है तथा इसे कब से चालू किया गया है,

(ख) जिले के कितने स्थानों को इस प्रणाली के साथ जोड़ा गया है,

(ग) क्या इस प्रणाली द्वारा जशपुर नगर को गुमला (बिहार) के साथ जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृति देने में हुई प्रगित का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ)ः

(क)	स्थानों के नाम	जब से कार्यरत है
रायगढ़	जुलाई	97
गढ़घोण्डा	अप्रैल	98
फाथलगांव	अप्रैल	98
कुकरी	जून	98
धर्मजयगढ़	अप्रैल	98

(ख) पांच

(ग) जी नहीं

(घ) उपर्यूक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाया जाना

2938. **श्री बरजिन्दर सिंह**:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने से संबंधित नीति को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अनुसार अपनाया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाने संबंधी आरंभ कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य किस तिथि को आरंभ किया गया था तथा मार्च, 1997-98 के अंत तक कुल कितने गांवों में टेलीफोन कार्य कर रहे थे और वर्ष 1998-99 के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ)ः (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाओं का प्रावधान एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के प्रावधान के अतिरिक्त है। सरकार द्वारा निम्न उपायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा हैः-

(1) टेलीफोन लाइने प्रदान करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना।

(2) देश के सभी गांवों को बुनियादी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मांग न होने पर भी आम जनता के प्रयोग हेतू प्रत्येक गांव में कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 से काफी पहले से टेलीफोन काम कर रहे थे। इसलिए इस काम को शुरु करने की कोई तारीख नहीं दी जा सकती । तथापि, 31.3.1998 तक कुल 3.10.697 गांवों में कम से कम एक सार्वजिनक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Population Served by PCOs

2939. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state: